



करंट अफियरा

उत्राश्वंड

दिसंबर 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

375E24

उत्त	उत्तराखंड	
>	कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में निगरानी प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग	3
>	उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाएगी घर	4
>	उत्तराखंड की नीति घाटी में बढ़ रहा ग्लेशियर	4
>	उत्तराखंड में ग्रीन सेस	5
>	उत्तराखंड में भूस्खलन क्षेत्रों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया	6
>	मसूरी में छठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम	7
>	10वाँ विश्व आयुर्वेद कॉन्प्रेस और आरोग्य एक्सपो	8
>	उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड	11
>	उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू	12
>	उत्तराखंड की वाइन टूरिज्म पहल	13
>	उत्तराखंड में वनाग्नि में वृद्धि	13

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025



UPSC क्लासरूम कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स मॉडयूल कोर्स





दृष्टि लर्निंग ऐप



उत्तराखंड

कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में निगरानी प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग

चर्चा में क्यों?

एनवायरनमेंट एँड प्लानिंग एफ नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के वन रेंजरें ने स्थानीय महिलाओं पर निगरानी रखने और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों को इकट्ठा करने से रोकने के लिये जानबूझकर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि वे कानुनी रूप से इन संसाधनों तक पहुँचने की हकदार थीं।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन का महत्त्वः
 - ♦ अध्ययन से पता चला िक निगरानी प्रौद्योगिकियाँ उन स्थानीय महिलाओं के मानिसक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं जो दैनिक गतिविधियों के लिये वनों पर निर्भर हैं।
 - ◆ यह अध्ययन प्रौद्योगिकी, संरक्षण और सामाजिक समानता के अंतर्संबंध पर प्रकाश डालता है तथा हितधारकों से अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करता है।
- महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याएँ:
 - इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हालाँकि कैमरा ट्रैप जैसी प्रौद्योगिकियाँ वन्यजीव निगरानी में आम हैं, लेकिन वे अनजाने में गोपनीयता का उल्लंघन कर सकती हैं और मानव व्यवहार को बदल सकती हैं।
 - ये निष्कर्ष इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं कि ऐसे उपकरण स्थानीय समुदायों को नुकसान न पहुँचाएँ।
- अनुशंसाएँ:
 - ◆ उत्तर भारत में महिलाओं की पहचान उनकी दैनिक वन गतिविधियों से गहराई से जुड़ी हुई है, जिससे संरक्षण प्रयासों में उनके दृष्टिकोण पर विचार करना महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
 - ★ संरक्षण रणनीतियों में वन्यजीव निगरानी और स्थानीय समुदायों की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा।

कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व

- परिचय:
 - यह उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर को वर्ष 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क (भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान) में लॉन्च किया गया था, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।
 - इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिये हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई
 थी।

रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025



UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर मॉडयल कोर्स





दृष्टि लर्निंग 🍃



- इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- ♦ मुख्य क्षेत्र **कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाता है, जबकि बफर क्षेत्र में आरक्षित वन** तथा सोनानदी वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।
- रिजर्व का पुरा क्षेत्र पहाडी है और शिवालिक एवं बाह्य हिमालय भुगर्भीय प्रांतों में आता है।

वनस्पतिः

◆ सघन नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारतीय वनस्पित सर्वेक्षण के अनुसार, कॉर्बेट में पादपों की 600 प्रजातियाँ हैं - वृक्ष, झाड़ियाँ, फ़र्न, घास, जड़ी-बृटियाँ और बाँस। साल, खैर और शीशम के वृक्ष कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वृक्ष हैं।

जीव-जंत:

◆ बाघों के अलावा कॉर्बेट में <mark>तेंद्र</mark> भी हैं । अन्य स्तनधारी जानवर जैसे जंगली बिल्लियाँ, <mark>बार्किंग डियर, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण</mark>, आदि भी वहाँ पाए जाते हैं।

उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाएगी घर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में, उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत कम आय वाले परिवारों के लिये 16,000 किफायती आवासों के निर्माण की घोषणा की है।

मुख्य बिंद्

PMAY परियोजनाः

- ♦ इस परियोजना का नेतृत्व उत्तराखंड आवास विकास परिषद (UHDC) और मसुरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) द्वारा किया जा रहा है।
- 🔷 ये निकाय इन घरों का समय पर और कुशल निर्माण सुनिश्चित करने के लिये निजी निवेशकों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।
- इस पहल में निजी निवेशकों द्वारा संचालित **15 परियोजनाएँ शामिल हैं.** जिनमें 12.856 आवास (घर) शामिल हैं, जबिक विभिन्न विकास प्राधिकरण अतिरिक्त 3,104 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं। मार्च 2025 तक सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

PMAY के बारे में:

- ◆ इस पहल का उद्देश्य बेघर परिवारों को 'पक्के' घर (आवास) उपलब्ध कराना है, जो 'अंत्योदय' के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है तथा गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना है।
- यह योजना 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले बेघर परिवारों के लिये बनाई गई है।
- पात्र परिवार 15 जून, 2015 से पहले से उत्तराखंड के निवासी होने चाहिये।
- इन किफायती आवासों का निर्माण उत्तराखंड में निम्न आय वाले परिवारों की जीवन स्थितियों में महत्त्वपूर्ण सुधार लाने की आशा है।

उत्तराखंड की नीति घाटी में बढ़ रहा ग्लेशियर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक उल्लेखनीय खोज में वैज्ञानिकों ने **उत्तराखंड की नीति घाटी** में तेज़ी से विस्तृत हो रहे <mark>ग्लेशियर</mark> की पहचान की है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुडें

मेन्स टेस्ट सीरीज









ष्टि लर्निंग



• "बहु-कालिक उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए मध्य हिमालय में ग्लेशियर वृद्धि की अभिव्यक्तियाँ" शीर्षक वाले अध्ययन में ग्लेशियर के तीव्र विकास को देखने के लिये उपग्रह चित्रों का उपयोग किया गया।

मुख्य बिंदु

- यह नया ग्लेशियर, जो लगभग 10 किलोमीटर लंबा और लगभग 48 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है, भारत-तिब्बत सीमा के समीप,
 राज्य के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में रैंडोल्फ और रेकाना ग्लेशियरों के निकट स्थित है।
- ग्लेशियर में वर्तमान में "उछाल" का अनुभव हो रहा है, अर्थात ग्लेशियर के आकार में अचानक और तीव्र वृद्धि, जो जल विज्ञान संबंधी असंतुलन के कारण हो सकती है।
 - ये असंतुलन तब होता है जब पानी बर्फ की परतों में घुस जाता है, जिससे वे कमज़ोर हो जाती हैं और बर्फ नीचे की ओर खिसकने लगती है।
- इस तेजी से बढ़ते ग्लेशियर की खोज से क्षेत्र के पर्यावरण और जलवायु पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ।
 - ♦ हिमनदीय उछाल से हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) का संकट बढ़ सकता है, जो निचले इलाकों के समुदायों और बुनियादी ढाँचे के लिये खतरा उत्पन्न करता है।
 - प्रभावी शमन रणनीति विकसित करने के लिये ऐसे ग्लेशियरों की गतिशीलता को समझना महत्त्वपूर्ण है।
 - जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की गति अप्रत्याशित होती जा रही है, जिसके लिये निरंतर निगरानी और अध्ययन की आवश्यकता है।

उत्तराखंड में ग्रीन सेस

चर्चा में क्यों?

अधिकारियों के अनुसार, **उत्तराखंड सरकार जल्द ही** राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों पर <mark>हरित उपकर</mark> लगाएगी।

ग्रीन सेस एक प्रकार का कर है जो सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से लगाया जाता है।

मुख्य बिंदु

- उत्तराखंड में हरित उपकर की शुरूआत:
 - यह उपकर 20 रुपए से 80 रुपए तक होगा और यह वाणिज्यिक और निजी दोनों वाहनों पर लागू होगा।
 - दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और उत्तराखंड में पंजीकृत वाहनों को छूट दी जाएगी।
- कार्यान्वयन और प्रौद्योगिकी:
 - ◆ इस प्रणाली को दिसंबर 2024 के अंत तक सिक्रय करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है।
 - स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे वाहनों की पहचान करेंगे और उपकर राशि सीधे वाहन मालिकों के फास्टैग वॉलेट से काट ली जाएगी।

फास्टैग (FASTag)

 यह एक ऐसा उपकरण है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग कर वाहन चलते समय सीधे टोल भुगतान करता है।

रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025



UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर मॉडयल कोर्म



हष्टि लर्निंग



- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिये दो मोबाइल ऐप-माईफास्टैग और फास्टैग पार्टनर लॉन्च किये।
- यह टैग जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक मान्य रहता है और यह सात विभिन्न रंगों के कोड में उपलब्ध है।

उत्तराखंड में भूस्खलन क्षेत्रों का सफलतापूर्वक उपचार किया गया

चर्चा में क्यों?

सीमा सड़क संगठन (BRO) के अनुसार, **रॉक बोल्ट तकनीक** उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सिक्रय भूस्खलन क्षेत्रों का सफलतापूर्वक उपचार कर रही है।

मुख्य बिंदु

- उत्तराखंड में भूस्खलन की चुनौतियाँ:
 - ◆ पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर मानसून के मौसम में, भूस्खलन की घटनाएँ नियमित रूप से होती रहती हैं, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं और चारधाम तीर्थयात्रियों को असुविधा होती है।
 - ♦ इन भूस्खलनों के परिणामस्वरूप प्राय: मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुँचता है और यह एक दीर्घकालिक चिंता का विषय बना हुआ है।
 - ♦ गंगोत्री और यमुनोत्री राजमार्गों पर लगातार भूस्खलन क्षेत्र वर्षों से बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।
- ऑस्ट्रेलियाई रॉक बोल्ट प्रौद्योगिकी को अपनानाः
 - ♦ BRO उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राजमार्ग पर रतूड़ीसेरा और बंदरकोट में सिक्रय भूस्खलन क्षेत्रों के उपचार के लिये ऑस्ट्रेलियाई रॉक बोल्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।
 - ◆ इससे पहले, इस तकनीक को नलूपानी और चुंगी बडेथी भूस्खलन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया था।
 - ◆ यह प्रौद्योगिकी चारधाम सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत वर्षों से सिक्रय भूस्खलन क्षेत्रों के उपचार में सहायक रही है।
- प्रभावशीलता और तकनीक:
 - भूस्खलन को रोकने में यह तकनीक 90% प्रभावी रही है।
 - ◆ इसमें ढीली मृदा को स्थिर करने के लिये मिट्टी में कील ठोंकना तथा कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करने के लिये आधारशिला में चट्टान बोल्ट लगाना शामिल है।

सीमा सड़क संगठन (BRO)

- 1960 में केवल दो परियोजनाओं, **पूर्व में प्रोजेक्ट टस्कर (अब वर्तक) और उत्तर भारत में प्रोजेक्ट बीकन के साथ स्थापित** BRO अब एक जीवंत संगठन बन गया है, जिसकी 11 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 18 परियोजनाएँ चल रही हैं।
 - ♦ अब इसे उच्च ऊँचाई वाले तथा बर्फ से घिरे दुर्गम क्षेत्रों में अग्रणी बुनियादी ढाँचा निर्माण एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- वर्ष 2023-24 में, BRO ने 125 बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ पूरी कीं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा-चारद्वार-तवांग रोड पर सेला सुरंग का निर्माण भी शामिल है।
 - BRO जल्द ही 4.10 किलोमीटर लंबी शिंकुन ला सुरंग का निर्माण शुरू करेगा, जो पूरा हो जाने पर 15,800 फीट की ऊँचाई पर दुनिया की सबसे ऊँची सुरंग बन जाएगी, जो 15,590 फीट की ऊँचाई पर स्थित चीन की मिला सुरंग को पीछे छोड़ देगी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025



UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर्स मॉडयल कोर्स



दृष्टि लर्निंग



- BRO **रक्षा मंत्रालय के अधीन एक भारतीय कार्यकारी बल है,** जिसका कार्य भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना तथा उत्तर और उत्तर-पूर्वी राज्यों के दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।
- यह सीमा सड़क विकास बोर्ड (BRDB) के अधीन कार्य करता है तथा सीमावर्ती क्षेत्रों और पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क के लिये जिम्मेदार है।
- BRO का आदर्श वाक्य है "श्रमेण सर्वं साध्यम्" जिसका अर्थ है "कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।"

मसूरी में छठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **श्रीलंका समाजवादी गणराज्य के सिविल सेवकों** के लिये <mark>छठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम</mark> मसूरी में **राष्ट्रीय सुशासन केंद्र** (NCGG) में शुरू हुआ।

मुख्य बिंदु

- कार्यक्रम की अवधि एवं प्रतिभागी:
 - यह कार्यक्रम 9 से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा।
 - ♦ इस कार्यक्रम में श्रीलंका के 40 मध्य-कैरियर सिविल सेवक भाग ले रहे हैं, जिनमें विभागीय सिचव, सहायक विभागीय सिचव, जिला सिचव तथा लोक प्रशासन, गृह मामले, कृषि एवं पशुधन तथा स्वास्थ्य जैसे प्रमुख मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हैं।
 - ◆ प्रतिभागियों में श्रीलंका विकास प्रशासन संस्थान (SLIDA) के अधिकारी भी शामिल हैं।
 - ♦ कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और प्रशासन की व्यापक समझ प्रदान करना है।
- सत्र निम्नलिखित पर केंद्रित होंगे:
 - बुनियादी प्रशासन
 - स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक प्रशासन में नीतिगत ढाँचे।
 - शासन में प्रौद्योगिकी, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की भूमिका।
 - सफल शासन मॉडल, जिसमें शहरी और गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपिशष्ट प्रबंधन की अंतर्दृष्टि के साथ अपिशष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ शामिल हैं।
- कवर किये गये विषयों में शामिल हैं:
 - शासन के परिवर्तित मानक
 - ई-ऑफिस, आयुष्पान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
- रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA), जलवायु परिवर्तन प्रभाव, आधार।
- महत्त्वपूर्ण संस्थानों का क्षेत्रीय दौरा जैसे:
 - ♦ वन अनुसंधान संस्थान (FRI), जिला प्रशासन गाजियाबाद और साइबर सुरक्षा सेल नोएडा।
 - ग्लोबल रोबोटिक्स कंपनी, पीएम गित शिक्त अनुभूति केंद्र, भारत मंडप और प्रधानमंत्री संघ्रालय।
 - ताजमहल की यात्रा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़



UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर मॉडयल कोर्स





दृष्टि लर्निंग ऐप



- NCGG की वैश्विक प्रशिक्षण भूमिकाः
 - वर्ष 2014 में स्थापित NCGG ने 214 वरिष्ठ श्रीलंकाई अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।
 - ◆ इसने मलेशिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और फिजी सहित 34 देशों के अधिकारियों को शासन प्रशिक्षण प्रदान किया है।

आयुष्मान भारत-PMJAY

- पीएम-जेएवाई **दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है** जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- फरवरी 2018 में लॉन्च की गई यह योजना द्वितीयक और **तृतीयक देखभाल के लिये प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान** करती है।
 - स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और डे केयर उपचार, दवाओं और निदान की लागत शामिल है।

10वाँ विश्व आयुर्वेद कॉन्प्रेस और आरोग्य एक्सपो

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कॉन्प्रेस (WAC 2024) और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया। यह एक महत्त्वपूर्ण मोड़ है जहाँ विभिन्न विचारधाराओं, संसुकृतियों और नवाचारों की धाराएँ मिलती हैं।

मुख्य बिंद्

- "देश का प्रकृति संरक्षण अभियान" का शुभारंभ:
 - ♦ 9वें आयुर्वेद दिवस (29 अक्तूबर, 2024) के अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री ने राष्ट्रव्यापी अभियान "देश का प्रकृति परीक्षण अभियान" का शभारंभ किया।
 - इसका उद्देश्य आयुर्वेद सिद्धांतों का उपयोग करके 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की प्रकृति का आकलन करना है।
 - नागरिकों को इस महान पहल में सिक्रय रूप से भाग लेने और योगदान देने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- आयुष ग्रिड और वैश्विक निवेश:
 - ♦ आयुष ग्रिड आयुष क्षेत्र को डिजिटल बनाने और पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिये आयुष मंत्रालय की एक परियोजना है।
 - ◆ इसके लाभों में नवाचारों के साथ स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाना, प्रभावशीलता, सुरक्षा और सामर्थ्य में वृद्धि करना शामिल है।
 - ♦ आयुर्वेद से संबंधित पहलों को समर्थन देने के लिये वैश्विक साझेदारों की ओर से 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश प्रस्तावित है।
- WAC 2024:
 - ◆ विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन (WAF) द्वारा आयोजित, जो विज्ञान भारती की एक पहल है।
 - 🔷 इस कार्यक्रम के लिये 5500 से अधिक भारतीय प्रतिनिधियों और 54 देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया।
 - इस कार्यक्रम में 150 **से अधिक वैज्ञानिक सत्र और 13 सहयोगी कार्यक्रम शामिल हैं,** जिनमें पूर्ण चर्चाएँ भी शामिल हैं।

रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

नेन्स टेस्ट सीरीज









ष्टि लर्निंग



- इसका विषय है "Digital Health: An Ayurveda Perspectiveअर्थात् डिजिटल स्वास्थ्यः आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य" जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने पर केंद्रित है।
- विचार-विमर्शः
 - डिजिटल उपकरणों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाना।
 - अनुसंधान पद्धितयों को पुनः परिभाषित करना।
 - आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य परिदृश्य में एकीकृत करना।
- आयुष मंत्रालय की भूमिकाः
 - ◆ आयुष मंत्रालय विश्व आयुर्वेद कॉन्प्रेस के आयोजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो विश्व स्तर पर आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
- योगदानः
 - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आयुर्वेद ज्ञान, अनुसंधान और प्रथाओं को आगे बढ़ाना।
 - आयुर्वेद की वैश्विक प्रासंगिकता और भिवष्य के विकास पर चर्चा करने के लिये विशेषज्ञों, चिकित्सकों और नीति निर्माताओं को शामिल करना।
- WAC 2024 का महत्त्व:
 - ◆ आयुर्वेद की समृद्ध विरासत का जश्न मनाता है और वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में इसके भविष्य की कल्पना करता है।
 - ♦ पारंपिक ज्ञान को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि आयुर्वेद एक स्थायी और समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के रूप में विकसित हो।
 - ♦ WAC 2024 आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण आयोजन है।

विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन (WAF)

- यह एक ऐसा संगठन है जो विश्व स्तर पर आयुर्वेद को बढ़ावा देता है और आयुर्वेद से संबंधित अनुसंधान, स्वास्थ्य कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों का समर्थन करता है।
- यह **विज्ञान भारती** की एक पहल है जिसकी **स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी।** WAF के उद्देश्यों में शामिल हैं:
 - अनुसंधान का समर्थन
 - ♦ शिविरों, क्लीनिकों और सेनेटोरियम के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यक्रमों का समर्थन करना
 - सेमिनार, प्रदर्शनियाँ और अध्ययन समूहों का आयोजन
 - आयुर्वेद के लिये नीति और योजना में नेतृत्व प्रदान करना
- WAF विश्व आयुर्वेद कॉन्प्रेस (WAC) का आयोजन करता है, जो एक ऐसा आयोजन है जिसमें वैज्ञानिक सत्र, स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन और अन्य गतिविधियाँ शामिल होती हैं।
- WAC का उद्देश्य इस बात पर चर्चा करना है कि आयुर्वेद विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025



UPSC क्लासरूम



IAS करेंट अफेयर मॉडयल कोर्स





दृष्टि लर्निंग 🍃





दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025



सिद्धांतों पर आधारित

को प्रोत्साहित करता है

UPSC क्लासरूम कोर्सेस

रोग-केंद्रित दिष्टिकोण के स्थान पर व्यक्ति-केंद्रित दिष्टिकोण





IAS करेंट अफेयर्स मॉडयल कोर्स



दृष्टि लर्निंग ऐप

Drishti IAS



नोट :

उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी।

• राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोज़गार में समान अवसर प्रदान करने के लिये एक नीति लाएगा।

मुख्य बिंदु

- सर्वेक्षण एवं पहचान-पत्र जारी करनाः
 - ♦ राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या की पहचान और पता लगाने के लिये पूरे उत्तराखंड में एक सर्वेक्षण कराया जाएगा।
 - सर्वेक्षण के बाद, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनकी औपचारिक पहचान के लिये पहचान-पत्र जारी किये जाएँगे।
- कल्याणकारी पहुँच को सुगम बनानाः
 - ♦ कल्याण बोर्ड **ट्रांसजेंडर समुदाय की** मौजूदा सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चित करेगा।
 - यह समुदाय के प्रति संवेदनशील और गैर-भेदभावपूर्ण नई योजनाएँ भी विकसित करेगा।
 - ◆ शिकायतों के समाधान के लिये एक प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसमें शिकायत समाधान के लिये एक निश्चित समय सीमा होगी।
- उत्तराखंड ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड का गठनः
 - समाज कल्याण विभाग प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करेगा, जबिक मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।
 - ♦ सदस्यों में समाज कल्याण, गृह, वित्त, कार्मिक, शहरी विकास और पंचायती राज जैसे विभागों के सचिव शामिल होंगे:
 - ट्रांसजेंडर समुदाय के पाँच विशेषज्ञ।
 - ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिये काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का एक प्रतिनिधि।
 - राष्ट्रीय संदर्भ और कानूनी अधिदेश।
- कल्याण बोर्ड स्थापित करने वाला 18वाँ राज्यः
 - ◆ उत्तराखंड ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और नियम, 2020 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये कल्याण बोर्ड स्थापित करने वाला 18वाँ राज्य ∕ केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।
 - ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड वाले अन्य राज्य हैं राजस्थान, मिजोरम, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तिमलनाडु, जम्मू-कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार।

ट्रांसजेंडर

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत ट्रांसजेंडर का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता।
- इसमें अंतरिलंगीय भिन्नता वाले ट्रांस-व्यक्ति, <mark>लिंग-विषमलेंगिक</mark> और किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले लोग शामिल हैं।

रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़



UPSC क्लासरूम कोर्मेम



IAS करेंट अफेयर मॉडयुल कोर्स









भारत की 2011 की जनगणना देश की पहली जनगणना थी जिसमें देश की 'ट्रांस' आबादी की संख्या को शामिल किया गया था।
 रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि 4.8 मिलियन भारतीय ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाते हैं।

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **मुख्यमंत्री** ने देहरादून में एक बैठक में घोषणा की कि **जनवरी 2025 से पूरे उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC)** लागू की जाएगी।

मुख्य बिंदु

- समान नागरिक संहिताः
- परिचय:
 - ♦ समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के भाग के रूप में रेखांकित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिये समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये।
 - ♦ हालाँकि, इसका कार्यान्वयन सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
- ऐतिहासिक संदर्भः
 - अंग्रेज़ों ने भारत में एक समान आपराधिक कानून स्थापित किये, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कानूनों को उनकी संवेदनशील प्रकृति के कारण मानकीकृत करने से परहेज किया।
 - बहस के दौरान संविधान सभा ने समान नागरिक संहिता पर चर्चा की और मुस्लिम सदस्यों ने सामुदायिक व्यक्तिगत कानूनों पर इसके प्रभाव के संबंध में चिंता व्यक्त की तथा धार्मिक प्रथाओं के लिये सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा।
 - दूसरी ओर के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी और बी.आर. अंबेडकर जैसे समर्थकों ने समानता को बढ़ावा देने के लिये समान नागरिक संहिता की वकालत की।
- मील का पत्थर उपलब्धिः
 - ◆ उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
 - गोवा भारत का एकमात्र राज्य था जहाँ 1867 के पूर्तगाली नागरिक संहिता के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू थी।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का UCC के प्रति दृष्टिकोण:

- मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम केस, 1985: न्यायालय ने खेद के साथ कहा कि "अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र बन कर रह गया है" और इसके कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया।
- सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, 1995 और जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ, 2003: न्यायालय ने UCC को लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि तीन तलाक की प्रथा असंवैधानिक है और मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और समानता का उल्लंघन करती है।
- इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि संसद को मुस्लिम विवाह और तलाक को विनियमित करने के लिये कानून पारित करना चाहिये।
- जोस पाउलो कॉउटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटिना परेरा केस, 2019: न्यायालय ने गोवा की प्रशंसा एक "उज्ज्वल उदाहरण" के

टिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ > GRANME UPSC क्लासरम कोसँस SCANME SCANME SCANME SCANME

रूप में की, जहाँ "समान नागरिक संहिता सभी पर लागू होती है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सिवाय कुछ सीमित अधिकारों की रक्षा के" और परे भारत में इसके कार्यान्वयन का आह्वान किया।

उत्तराखंड की वाइन टूरिज़्म पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने **वाइन ट्रिज़्म (वाइन पर्यटन) को** बढ़ावा देने के लिये अपनी **नई आबकारी नीति** के तहत **कोटद्वार** में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

- वाइन टूरिज़्म पहल:
 - ♦ इस पहल का उद्देश्य वाइन प्रेमियों को वाइन उत्पादन इकाइयों का दौरा करने, वाइन के इतिहास के बारे में जानने, उत्पादन प्रक्रिया को समझने और विभिन्न प्रकार की वाइन का स्वाद लेने का अवसर प्रदान करना है।
 - ◆ **पर्यटन अनुभव को बढ़ाने के लिये वाइन इकाइयों के आसपास गेस्ट हाउस** विकसित किये जा रहे हैं, जिससे आगंतुकों को आराम करने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का अवसर मिलेगा।
- उत्तराखंड के कृषि संसाधनः
 - ♦ उत्तराखंड माल्टा, सेब, बुरांश फूल, नाशपाती और गलगल जैसे फलों से समृद्ध है, जिनका उपयोग शराब उत्पादन (Wine Production) के लिये किया जा सकता है।
 - चे स्थानीय संसाधन वाइन ट्रिज्म के लिये एक अद्वितीय आकर्षण बनाने में सहायता करेंगे।
- विस्तार योजनाएँ:
 - कोटद्वार में दो माह पूर्व एक प्राइवेट वाइन यूनिट स्थापित की गई है, जो आबकारी विभाग (Excise Department) की अनुमति से लगातार शराब का उत्पादन कर रही है।
 - बागेश्वर और चंपावत में नए वाइन उत्पादन संयंत्रों की योजना बनाई गई है।
- आर्थिक एवं रोज़गार उद्देश्य:
 - ♦ सरकार का उद्देश्य यह है कि आबकारी नीति के माध्यम द्वारा राजस्व में वृद्धि हो और रोज़गार के नए अवसर सृजित किये जाएँ।
 - ◆ पहाड़ी क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम वाइन उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे स्थानीय फलों का उपयोग करके स्थानीय लोगों के लिये रोजगार और व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे।

उत्तराखंड में वनाग्नि में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वनाग्नि में 74% की वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्य बिंदु

- उपग्रह अवलोकन और अग्नि दुर्घटनाओं की गणनाः
 - उत्तराखंड में, उपग्रह डेटा ने आग की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, नवंबर 2023 से जुन 2024 तक 21,033 आग की घटनाएँ हुईं, जबिक वर्ष 2022-2023 में इसी अवधि के दौरान 5,351 घटनाएँ हुईं।

रिष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

नेन्स टेस्ट सीरीज









दृष्टि लर्निंग



- इस मौसम के दौरान कुल 1,808.9 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र आग से प्रभावित हुआ।
- आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक आग प्रभावित क्षेत्र (5,286.76 वर्ग किमी.) दर्ज किया गया, उसके बाद महाराष्ट्र (4,095.04 वर्ग किमी.) और तेलंगाना (3,983.28 वर्ग किमी.), हिमाचल प्रदेश (783.11 वर्ग किमी.) का स्थान रहा।
- सर्वाधिक प्रभावित राज्य:

♦ छत्तीसगढ़: 18,950 घटनाएँ

आंध्र प्रदेश: 18,174 घटनाएँ

◆ महाराष्ट्रः 16,008 घटनाएँ

मध्य प्रदेश: 15,878 घटनाएँ

तेलंगानाः 13,479 घटनाएँ

- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रः
 - ♦ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को "अत्यंत उच्च जोखिम" वाले क्षेत्र घोषित किया गया।
- राष्ट्रव्यापी जोखिम:
 - ♦ भारत का लगभग 11.34% वन क्षेत्र और झाड़ी क्षेत्र अत्यंत से लेकर अत्यंत अग्नि-प्रवण क्षेत्रों में स्थित है, जिनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड के कुछ हिस्से संवेदनशील हैं।
- अग्नि संवेदनशीलताः
 - अत्यधिक गर्मी और ईंधन की लकड़ी की उपलब्धता जैसी जलवायु परिस्थितियाँ वनों में आग लगने की संभावना में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।
 - ♦ ज्वलनशील पदार्थों की उपस्थित के कारण आग अक्सर अन्य वन क्षेत्रों में तेज़ी से विस्तृत हो जाती है।
 - यह डेटा भारत में वनों की आग की बढ़ती गंभीरता को उजागर करता है, जिसके पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण

- स्थापना: 1 जून, 1981 को स्थापित, 1965 में शुरू किये गए वन संसाधनों के पूर्व निवेश सर्वेक्षण (PISFR) का स्थान लिया।
 - ◆ 1976 में, राष्ट्रीय कृषि आयोग (NCA) ने राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप FSI का निर्माण हुआ।
 - ◆ PISFR की शुरुआत वर्ष 1965 में भारत सरकार द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से की गई थी।
- मूल संगठनः पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार।
- प्राथिमक उद्देश्यः भारत के वन संसाधनों का नियमित रूप से आकलन और निगरानी करना।
 - ◆ इसके अलावा, यह प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार की सेवाएँ भी प्रदान करता है।
- कार्यप्रणाली: FSI का मुख्यालय देहरादून में है तथा शिमला, कोलकाता, नागपुर और बंगलौर में चार क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ इसकी उपस्थिति पूरे भारत में है।
 - पूर्वी क्षेत्र का एक उपकेंद्र बर्नीहाट (मेघालय) में है।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें





UPSC क्लासरूम कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर मॉडयल कोर्स



दृष्टि लर्निंग ऐप

